(d) to (g) Later an Agreement on principal terms signed with Oman in September, 1994. Oman will design, construct, finance, own and operate a deep-sea pipeline system to transport 56.6 MMSCMD of natural gas to India.

The start-up date for the first pipeline to carry 28.3 MMSCMD will be July 1, 1999. The second line will be completed 18-24 months thereafter. The landfall point for the gas will be at Ropar Garhwali in Gujarat. The price of the imported gas is not yet fully negotiated.

Under the Agreement the detailed feasibility study for the project was to be completed by July, 1995. The study is, however, yet to be completed. Delays are expected in the start-up date mentioned above.

Development of Solar Energy in Andhra Pradesh

2542. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have any plans to launch an accelerated solar energy development programme in Andhra Pradesh in 1996-97;

(b) whether it is a fact that Andhra Pradesh is lagging behind the other States in the use and production of solar energy; and

(c) if so, the steps proposed to be taken to enhance solar energy programme in Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (c) The Government has been implementing the solar energy programme all over the country, including in the State of Andhra Pradesh. Under the programme installation of various solar photovoltaic and solar thermal devices and systems is promoted. In Andhra Pradesh, 5963 solar lanterns, 2932 street lighting systems, 780 domestic lighting systems and 4 small SPV power plants, 9652 solar cookers, and solar water heating and desalination systems of aggregate 7500 sq. m. collector area have been installed as on 31.03.1996. The State is not lagging behind in the implementation of solar enrgy programme. During 1996-97, it is proposed to distribute 5000 solar lanterns, and instal 500 solar home lighting systems and 100 solar street lighting systems in the State.

मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किये गए निवेश का मूल्यांकन

2543. **श्री राघव जी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किए गए निवेश का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किये जाने का विचार है; और

(घ) क्या राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा उत्पादित खाद्य तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात की काफी संभावना है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) से (घ) मंत्रालय मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए स्वयं कोई मूल्यांकन नहीं करता लेकिन वह अपनी योजना स्कीमों के तहत ऐसे अध्ययन/सर्वेक्षण करने के लिए राज्य सरकारों, संस्थाओं और संगठनों को सहायता उपलब्ध कराता है। मध्य प्रदेश सरकार/वहां के किसी संगठन से ऐसे अध्ययन करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की व्यापक संभावनाएं हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ फल तथा सब्जी उत्पाद, सोया आधारित उत्पाद, स्नैक फूड, मांस तथा पाल्ट्री उत्पाद आदि शामिल हैं।

मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना नहीं करता। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नीतियों को उदार बनाया है और अल्कोहल पेयों के विण्वन और